[श्री रघुनाथ राय]

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि दिल्ली की आबादी को मद्देनजर रखते हुए वह पुलिस के और भी स्टेशन तथा सब-स्टेशन खोले ताकि दिल्ली के लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके ।

THE NATIONAL AIRPORTS AUTHORITY BILL, 1985—Contd.

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए यह कहना चाहूंगी कि इधर देश में विमान पत्तन की सेवा में काफी वृद्धि हुई है और ऐसा अंदाज किया जाता है कि 1990 तक इसमें 70 प्रतिशत इसको कैपेसिटी में वृद्धि होने का आशंका है । यह सराहनीय बात है ।

इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी फलीट है । उनकी एक्सपेंशन की योजना है । इस तरह एयरलाइंस के ग्रोथ में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि कल हमारे नौजवान मंत्री जी ने कहा कि लगभग 65 से भी अधिक हमारे एयरोड्रम्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन, मेंटनेंस और उनकी और सभी बातों को देखा जाए, क्योंकि हमारा काम बहुत बढ़ गया है और आगे भविष्य में भी बढ़ने वाला है। अतः इस बिल की अपनी अहमियत है। नेशनल इन्टेग्रेशन के ख्याल से भी हमारा यह ट्रैफिक एक स्थान रखता है। दिन प्रति दिन अगर हम इस निगम की अर्थ-व्यवस्था को देखें तो हमारी जितनी रेवेन्यू होती है, उसमें काफी सुधार है और इसके जितने भी जोन्स हैं, इंडियन एयरलाईंस के, उनकी सेल का जो टार्गेट फिक्स किया गया है, उनमें काफी संतोष-प्रद वृद्धि हुई है और उम्मीद की जाती है कि यह हमारा टार्गेट और अधिक बढ़ता रहेगा ।

लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है, वह इसके एक्सपेंशन को देखते हुए और एयर-ट्रैफिक की अहमियत को देखते हुए कुछ कम मालूम पड़ती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल-इण्टीग्रेशन के ख्याल से और एयर-ट्रैफिक का अपनी अहमियत रखते हैं । हमारे कारपोरेशन का जो अर्थव्यवस्था है, वह सुदृढ़ है और उसको देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि इसकी फंक्शनिंग में ओवर-आल इम्प्रूवमेंट हुआ है । इसमें ओवर-आल इम्प्रूवमेंट भी निहायत जरूरी है और जितने भी हमारे छोटे-बड़े एयरपोर्ट हैं, एयरोड्रम हैं, उनमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है । हमें अपने आगे भविष्य को देखते हुए जो हमारे एयरपोर्टस हैं, जो एयरोड्रम्स हैं, उनकी एक परस्पैक्टिव प्लैनिंग करनी चाहिए । आज एयरपोर्ट पर जाइए, उनके टर्मिनल बिल्डिंग को देखिए, तो वहां काफी भीड़ रहती है । जहां तक कि कभी कभी पैसेंजर को बैठने की सुविधा भी वहां नहीं रहती है और इसीलिए उस एयर-ट्रैफिक की अहमियत को देखते हुए आगे जो भी एयरपोर्ट बनाए जायें, उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनकी परस्पेक्टिव प्लैनिंग होनी चाहिए । जैसा कि मैंने बताया नेशनल इंटीग्रेशन के ख्याल से हमारा नार्थ-ईस्टर्न जोन जो है, उसकी जितनी तरक्की होनी चाहिए, उतनी अभी नहीं हो पायी है । गोहाटी एयरपोर्ट को आगे अपग्रेड करना चाहिए और नार्थ-ईस्टर्न रीजन के आर्थिक विकास की दृष्टि से और नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से उसको बांबे से लिंक करना चाहिए । यह एक पिछड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसका विकास होना चाहिए । यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी अहमियत को समझा और इसकी तरफ इनीसियेटिव लेकर हेलीकाप्टर कारपोरेशन की स्थापना की । हेलीकाप्टर कारपोरेशन होने से जितने भी उधर के पहाड़ी इलाके हैं, वह काफी जुड़ जाएंगे और वहां के लोगों को सुविधा

होगी। फिर भी गोहाटी का अपना एक स्थान है और उसके एअर-स्टेशन को आगे अपग्रेड करके, उसको एक जोन बनाकर के उसकी अहमियत को समझना चाहिए क्योंकि हमारे देश का आर्थिक विकास बढ़ रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है। आज अगर बंबे का कोई व्यवसायी गोहाटी जाना चाहता है, तो उसे बड़ी कठिनाई होती है, वह कुछ ही घंटों में लंदन पहुंच जाएगा, अमरीका पहुंच जायेगा, लेकिन गोहाटी के लिये उसको सोचना पड़ता है।

इन सारी बातों के साथ मैं अपने बिहार के पटना एअरपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहूंगा कि वहां पर एअरो-ब्रिज जो है बेगेज चेक करने की, वह डिफेक्टिव है, बेकार पड़ी हुई है। सिर्फ पटना की ही नहीं बल्कि ऐसे लगभग 12-16 स्टेशन एअर के हैं, जिनकी बेगेज चेकिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। साथ ही साथ वहां टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार है और लगभग छह महीने से अधिक से वहां ताला लगा हुआ है, जबकि आपके इंडियन-एअरलाइन्स का जो अधिकारी हैं, वह एक छोटे से कमरे में काम करते हैं जहां सारा कामकाज उनको देखना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से यह मेरा अनुरोध है कि उस टर्मिनल-बिल्डिंग को या तो इंडियन-एअरलाइन्स को हस्तांतरित करवा दें या उसकी उपयोगिता को काम में ले आया जाये। पटना एअरपोर्ट की एअर-फील्ड को भी बढ़ा दिया गया है, उसका रनवे बड़ा हो गया है, उसका एप्रन बन गया है, वहां पर एक एअर-बस उतर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को वहां अभी तक कोई एअर-बस की सहूलियत नहीं दी गयी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदया, अभी आप शिमला एअरपोर्ट की बात देखें। वहां 1 करोड़ 20 लाख की धनराशि से काम शुरु किया गया था। लेकिन शिमला स्टेट हेडक्वार्टर होते हुए भी, कैपीटल होते हुए भी अभी तक देश से जुड़ नहीं पाया है। इसलिए इसको भी जोड़ने की दिशा में कार्यवाही होनी चाहिए। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगी वह यह कि इस बिल में जो क्लाज 12 सी (I) में दिया गया है इसके फंक्शन्स के बारे में–

"provide air safety services and search and rescue facilities in co-ordination with other agencies"

इसके बारे में यह कहना था कि जहां तक विमान के अन्दर पैसिंजर्स को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उनमें सीक्योरिटी बहुत अहमियत रखती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत इनीशिएटिव लेकर एक सब-ग्रुप की स्थापना इसके लिए की थी और उसके सदस्यों ने विभिन्न एअरपोर्टों पर जाकर वहां के सीक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखा और अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन है कि उस रिपोर्ट को लागू करने की दिशा में कार्यवाही की जाय। जहां तक डायरेक्टर जनरल सीक्योरिटी का प्रश्न है, उन्हें इस बोर्ड के सदस्य के रूप में रहना चाहिए ताकि सीक्योरिटी से सम्बन्धित सारी बातें इसके तहत आ जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर अनुकूल कार्यवाही करने की दिशा में विचार करेंगे। धन्यवाद।

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairman, I rise in support of the Bill which aims at increasing expediency and efficiency of civil aviation. In fact an autonomous body was needed for this commercial organization. The Directorate-General of Civil Aviation is at present maintaining 65 aerodromes in the

[Shri Dharam Chander Prashant]

country—and this number may be increased—but in the 7th Plan the allocation of funds for civil aviation is to the tune of only Rs. 311 crores or a little more than that. This, I think, is less, and it should be increased by at least 40 per cent.

Madam, in my own State of Jammu and Kashmir there are two aerodromes—one in Srinagar and the other in Jammu. There is a very long-standing demand that the Srinagar aerodrome should be converted into an international aerodrome in view of the fact that a large number of tourists are coming from abroad to visit the Kashmir Valley. In Jammu there is one aerodrome but it is small and its airstrip is very short and fit only for landing of Boeing aircraft and not Airbus which goes from Delhi to Srinagar direct. This airstrip should be enlarged. Then, the building of the Jammu aerodrome is small. When there is heavy rush of passengers, there is virtually a stampede inside the building and, therefore, this building should also be expanded.

Another demand of mine is that there should be a regular helicopter service between Katra and Vaishnodevi which 15 lakh pilgrims visit every year. Not to speak of the young, even old people of 90 and above visit this shrine of Vaishnodevi; not only the poor, the affluent people also visit this shrine. Therefore, a regular helicopter service to Vaishnodevi from Katra will not entail any loss, if such a service is started between Katra and Vaishnodevi for the facility of the pilgrims.

One more demand of mine is about air tickets. Air travel is costly and average people cannot afford to travel by air; only the rich can do so. Therefore, if you cannot decrease the cost of the air tickets so that average people also could travel by air, at least please give the facility of concessional travel to children, and students who are on study tours.

Another point is that security at the aerodromes should be further tightened in view of the hijacking incidents which are taking place all over the world. Only the other day fifty air passengers were killed in Malta due to a hijacking incident. Security arrangements at the aerodromes may be tightened, but the point to be remembered here is that while doing so there should be no harassment to the general air travellers. Sometimes the security men harass genuine travellers. They can easily distinguish who is genuine traveller and who is not or who is an unsocial element. There should be no harassment of genuine travellers.

With this, I conclude my speech.

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदया, हमारे युवा मंत्री जी सदन के सामने राष्ट्रीय विमान पत्तन प्रसारण विधेयक 1985 जो लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह उन्होंने अपना पहला विधेयक प्रस्तुत किया है और इस बात के लिए मैं उन का अभिनन्दन करते हुए इस विधेयक के समर्थन में कुछ बाते कहना चाहूंगा। वैसे सदन में कल बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला गया । मेरी जानकारी के मुताबिक और जो प्राविजन इस विधेयक में किये गये उन सब का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि एक डायनमिक मंत्री हम को मिले हैं और इसलिये जो बातें सदन में उपस्थित की गयी हैं उन पर जल्द से जल्द विचार कर के उन को पूरा कर पायेंगे ।

वैसे कल जिस बात को कहा गया उस को मैं दोहराना नही चाहूंगा इस लिये कि उस की भारी अहमियत है, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिस ढंग से काम कर रहा है उस में अधिक से अधिक तकलीफें आती हैं। कल इस बात को बहुत बार कहा गया है और इस लिये मैं उस में अधिक जाना नहीं चाहता, लेकिन उस की तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता है ।

टिकटों के बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे वी आई

पीज हैं या जो एम पीज हैं उनके लिये हम यह नही करना चाहते कि उन को किसी तरह की प्रायरिटी दी जाये, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी मर्तबा ऐसा होता हैं कि उन को बहुत कम वक्त मिल पाता है और पूरे मुल्क में उनकी संख्या बहुत कम है और उसमें मुसाफिरी करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वे ऐन वक्त पर ही पहुंच पाते है। इस के बाद भी हम यह नहीं चाहते कि उनको प्रायरिटी दी जाये, लेकिन हम सभी के साथ रह कर अपना अधिकार लेना चाहते हैं। लेकिन एक व्यवस्था की ओर मैं जरूर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो ऐसा करना चाहिए कि जो संसद सदस्य हैं उन के लिये या जो एम एल एज हैं उन के लिये अगर आप मुमकिन समझें, उन को जो बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है उस का एक अलग कलर रख दिया जाय तो वह सेक्योरिटी परपज के लिये ठीक होगा। कभी किसी की वेइज्जती हो जाती है, तो मैं समझता हुं कि सेक्योरिटी परपज के लिये भी यह उचित होगा कि उन के कार्ड का कलर अलग कर दिया जाये। तो इस से उन को कुछ सुविधा हो जायगी।

जहां तक बैगेजेज का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जो सामान होता है उस को बहुत बेरहमी के साथ पटका जाता है और तोड़ा जाता है और वह जब हम लोगों को मिल जाता है तभी हम को राहत मिलती है कि हमारा सामान ठीक ढंग से आ गया है। तो इसके लिये मैं खासतौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस के लिये कोई ऐसा सिस्टम बनायें कि मुसाफिरों का सामान सलामती के साथ हैंडिल किया जाये और उस को मुसाफिरों को दिया जाये।

जैसा कि मेरे दूसरे साथियों ने कहा है, कैटरिंग की जो व्यवस्था है मैं समझता हूं कि वह बहुत घटिया किस्म की है। जहां तक जूस का ताल्लुक है, हम उतने पैसे वाले तो नहीं हैं कि अपने आप विमानों में यातायात कर सकें लेकिन सरकारी तौर पर जब हम सदन में आते हैं तो पाते हैं कि वहां मिलने वाले जूस का जो कलर है वह बहुत खराब है और उस को पीने से गला खराब हो जाता है। इस में सुधार होना चाहिए दूसरी एक और बात की जनरल चैकिंग होनी चाहिए कि जो ब्राउन पेपर प्रोवाइड किया जाता है वहां वह रहता ही नही है। मेरा मानना है कि कुछ साइन किये जाते हैं लेकिन वहां जा कर कोई ब्राउन पेपर मैंने देखी नहीं है तो इस की चैकिंग के लिये माननीय मंत्री जी को जरूर कुछ करना चाहिए।

जहां तक एयर क्राफ्ट की लैंडिंग का सवाल है हमारे साथी जब जब मुसाफिरी किये हैं उन का अनुभव है कि लैंडिंग इतनी घटिया किस्म की होती है कि जिस की वजह से मुसाफिरों को बड़ा डर लगता है और हमारे साथ भी यह बात घटी है। कितनी ही मर्तबा प्लेन के टायर बर्स्ट हो गये और रात को वहां ही रहना पड़ा और दूसरे दिन सुबह दिल्ली वापस आना पड़ा। तो मेहरबानी कर के इस बात की खास तौर पर आप चैकिंग करवा लें। एक अहम सवाल मैं मंत्री जी से करना चाहता हूं जिसकी ओर वह कृपया ध्यान दें। केबिनक्रू की जो यूनियंस हैं उनमें जो भी मैजारिटी के लोग हैं, मैजारिटी उन्होंने आपको बता दी है, तहकीकात भी हो चुकी है, लेकिन मैजारिटी रखने के बाद भी केबिनक्रू को आपने रिकागनिशन नहीं दी है जैसा कि डैमोक्रेसी में होता है मैजारिटी को मानना पड़ता है, तो मैजारिटी की यूनियन को आप रिकागनाइज कीजिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, जो मैजारिटी रखता हो उसको स्वीकृति दे दें और उसको काम करने की अनुमति दें।

मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि आज देश में कलाकार और पोर्ट्समेन देश का नाम रोशन करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको प्रोक्योरिटी देकर, नौकरियों में भरती करना चाहिए। अगर अप्लीकेशन भी उन्होंने नहीं दी है तो उनको ढूंढ ढूंढकर लाकर नौकरियों में सुविधा देनी चाहिए।

[श्री मीर्जा इर्शादबेग]

श्रीमन्, मैं जहां से आता हूं, अहमदाबाद का दिल्ली और बम्बई पर अधिक बोझ है। इसलिए अहमदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्वीकृति दे दी जाये तो मैं समझता हूं जितना और एयरपोर्टों पर लोड है वह कम हो सकेगा और यात्रियों को भी सुविधा हो सकेगी। इसी तरह गुजरात से भी बहुत से मुसाफिर सफर करते हैं। उसको भी अंतर्राष्ट्रीय ऐयरपोर्ट का दर्जा दे दिया जाए तो उचित होगा। इसके साथ ही बैगेज की कोई ऐक्सरे मशीन अहमदाबाद में नहीं लगी है। मैं चाहूंगा कि तुरन्त उसका भी प्रबंध किया जाना चाहिए।

जहां तक तीर्थ यात्रियों का सवाल है, हज पिलग्रिमेंट के बारे में बहुत सी शिकायतें हमारे सामने पेश आई हैं। उनके साथ जो वर्ताव होता है, वह ठीक नहीं है। उनके साथ अच्छा व्यवहार हो इसके लिए आप अथारिटीज को निर्देश दें।

महोदया, विमान के किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस गति से बढ़ रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को उनमें सफर करना कठिन हो रहा है। मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्राफिट होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भी तो यात्रियों को देनी चाहिएं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर किराए नहीं घटा सकते तो उनकी सुविधाएं बढ़ा दीजिए।

हमारे जो लोग कभी बड़े समारोहों में या उत्सवों में या पिलग्रिमेज के सेंटर्ज में वेकेशंस में जाना चाहते हैं तो ऐसे कम से कम स्पैशल फ्लाइट्स आप चलाइए, कम किराये या कंशेशनल रेट्स पर चलाइये ताकि एक दूसरे राज्य के लोग नजदीक आ सकें और एक दूसरे की संस्कृति जान सकें। वे यह जान सकें कि हमारा हिन्दुस्तान कितना महान है। इसलिए स्पेशल फ्लाइट्स को सस्ते दरों पर आप व्यवस्था कीजिए।

मैं एक खास निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं हवाई अड्डों के, जैसाकि और देशों में है मैं अभी ताशकंद गया था, वहां का मैट्रो स्टेशन देखकर मालूम पड़ जाता है कि वहां की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐरोड्रोम पर यात्री पहुंचे तो उस राज्य की संस्कृति क्या है वह पता लग जाना चाहिए, वह एरोड्रोम में देखने को मिल जाना चाहिए। वहां के कंस्ट्रक्शन में वहां के जुशोभन में वहां की संस्कृति ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पर देखने को मिल सके, इसकी आप व्यवस्था करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जब एयरपोर्ट पर बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। हमारे यहां की एयर होस्टेस अगर हिन्दी में बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेज इंसान बैठकर हिन्दी बोल रहा है। इसका प्रोनांसियेशन अच्छा होना चाहिए। अगर अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं तो हिन्दी भी अच्छी तरह बोलनी चाहिए। जैसाकि ट्रेनों में होता है। क्या यह मान लेना जरूरी है कि लिटरेट लोग ही उनमें सफर करते हैं ? . . .

उपसभापति : मेरा सुझाव है कि इनकी हिन्दी बहुत अच्छी है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाए। ये एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दे सकेंगे। . . . . (व्यवधान)

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मैं आभारी होऊंगा। . . . (व्यवधान)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता से जो ट्रेन चलती है तो उसका एनाउंसमेंट बंगला में वहां पर होता है और जब गुजरात में दाखिल हो जाती है तो उसका एनाउन्समेंट गुजराती में हो जाता है तो इसी तरह से रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए क्या इस बात को हमारे विमान सर्विस पर लागू नहीं कर सकते ? मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा हिन्दी उन को सुधारें। हमने यह पाया है कि उनमें कुछ गरीब लोग होते हैं, गरीब इन्सान होते हैं वे जब कोई

पूछते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा कि अच्छा इंगलिश बोलने वाले के साथ, या सूटिड-बूटिड वाले के साथ किया जाता है । और अगर किसी ने गरीब इन्सान ने पानी मांग लिया तो उसको आधे घंटे के बाद दिया जाता है । कहीं अगर विमान की सर्विस लेट हो गई और वहां पर खाने का समय हो गया है लेकिन विमान के शेड्यूल्ड के मुताबिक उनका नाश्ते का समय है तो वह नाश्ता ही देंगे, खाना नहीं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर वह गौर करें। वह गौर करेंगे हमें सम्पूर्ण आशा है । आप इस के साथ अधिक से अधिक सम्मिलित रहे हैं । इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बात पर ध्यान रख कर, गौर करके इसको निपटाने की कोशिश करेंगे और यातायात की अधिक सुविधाओं का प्रोविजन करा सकेंगे । इतना ही कहना चाहता हूं । धन्यवाद

उपसभापति : धाबे जी, आपने नाम दिया लेकिन आपकी पार्टी के दो मिनट हैं और आप दो मिनट में बोल नहीं सकते । आप कह दीजिए कि जैसा उन्होंने कहा वह हमने कह दिया ।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I have followed what you have said. I want to speak about the problem of your own State only. Madam Deputy Chairman, this a very welcome Bill and it is a good step, a proper step to constitute Airports Authority. In fact, because of this dual and tripple system, the construction of airports and other matters are very much delayed. Coming from Nagpur, I know, the Central PWD was given the work of the expansion of the Airport. Sanction was made in the year 1984-85. Sanction has lapsed because even the plans and designs were not made and all problems are still awaiting solution due to the procedural delay in this department. Now, the time has come when the Civil Aviation has come to stay. It must have more consultations with the passengers and those who are using the aircrafts. In Railways, we have got Advisory Committees—in Central Railway, in South Eastern Railway and others. I therefore, suggest that for every Airport Authority, whether at Bombay or at Nagpur, Advisory Committees, including the Members of Parliament, representatives of the passengers and the representatives of the commercial organisations should be formed so that they can solve their problems on the spot and today, unfortunately, there is no machinery in the Indian Airlines to ventilate the grievances of the passengers, who are using these planes and therefore, it is high time that Advisory Committees, as are in existence in Railway Administration should be formed at every important Airport and at other places. The second question which I want to suggest is that the passenger amenities are very poor. Even reading material is not available in the evening flights. No magazines are given. The old newspapers which are sometimes brought from Calcutta and sometimes from Madras, are given. Therefore, there should be some systematic arrangement for giving the reading material including magazines like the Illustrated Weekly and others to these passengers, who have to travel for more than two hours. I am pained to say that Nagpur is one place which is totally neglected by Indian Airlines. Three days back, we have got Avro-service which takes 2 hours and 50 minutes to reach this place. I do not know whether the Madam has travelled by the Avro planes. She should experience the visit to Delhi *via* Nagpur and see as to what is the plight of the passengers. Now, Nagpur was connected with Bombay and Calcutta by morning flights. We used to get national newspapers from Bombay and similarly from Delhi because the morning flight from Madras to Delhi was stopping at Nagpur. Today, these flights have been stopped. Nagpur has no connecting flight with Madras. There is no morning flight going to Bombay. Even to Aurangabad, I cannot go. For that, I have to go to Bombay and then to Aurangabad be-

[Shri S. W. Dhabe]

cause the cities in Maharashtra State are not well connected by the Indian Airlines, and therefore, it is high time that the scheduled is changed, and that it must be only economically oriented or commercially oriented, that should not be the attitude. Public utility is the main objective of the Indian Airlines. Therefore, I suggest that a Boeing service should be started connecting Nagpur with all the metropolitan cities. Nagpur is the second Capital of Maharashtra. In Kashmir, Jammu is the second Capital and both Jammu and Srinagar are connected by Boeing. Even small cities like Imphal, Pondicherry and Panaji are having good flight services. Nagpur is an important city where the Assembly session is also held. Even then, in spite of several complaints, the airlines service to Nagpur has not improved. I suggest that at least the expansion of the airport at Nagpur should be done, expeditiously as it is a stand-by airport for international flights. Action should be taken immediately to see that Nagpur is well connected with the important cities in India. I, therefore, suggest to the Minister to look into all these problems seriously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): Madam, I would like, first of all, to thank all the Members...

SHRI B. L. PANWAR (Rajasthan): Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Panwar's name is there. I am sorry. I do not know what is happening to me. I have forgotten your name. Today is the day I am forgetting names. You may speak.

श्री सैयद रहमत अली (आंध्र प्रदेश): मुझे भी एक मिनट का टाइम दे दीजिए।

उपसभापति: आपका नाम तो है ही नहीं। जिनका नाम है उनका नाम भी मैं भूल रही हूं। श्री बी० एल० पंवार।

श्री भंवर लाल पंवार: उपसभापति महोदया, दी नेशनल एयर पोर्टस अथारिटी बिल, 1985 का स्वागत करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं भारत की युवा शक्ति के प्रतीक एवं विश्व नेता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा भारत को इक्कीसवीं सदी में ले जाने की प्रक्रिया में एक अच्छे कदम के रूप मे पाता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आकांक्षा करता हूं कि इस अथारिटी के माध्यम से भारत के ग्रामीण इलाकों को हवाई सुविधा से जोड़ा जायेगा ताकि उद्योगों का भी विकेंद्रीकरण हो सके और इसके साथ ही शहरों में जनसंख्या का भार कम हो सके। यह बिल इस बात का भी प्रतीक है कि भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है एवं भारत विकासशील देशों की श्रेणी से आगे बढ़ता हुआ विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है।

महोदया, इस बिल के संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं निम्न अनुरोध करना चाहूंगा। इस बिल की धारा 7 में सदस्य के पुनः नियुक्ति का प्रावधान है, परन्तु कितने टर्म तक के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार से धारा 11 में जो "आन बिजनेस प्रिंसिपल्स" के अनुसार कार्य करने का प्रावधान है। उसके आगे "एण्ड आन नो प्रोफिट बेसिस" जोड़ा जाना चाहिए। यद्यपि मैंने कोई एमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया है, फिर भी माननीय मंत्री महोदय स्वयं की ओर से इस धारा के नीचे एक्सप्लेनेशन जोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं अथवा नियमों या रेगुलेशन्स में इस प्रकार का प्रावधान या स्पष्टीकरण करने का सदन को आश्वासन दे सकते हैं।

महोदया, इस बिल के संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं निम्न अनुरोध भी करना चाहूंगा । जब विज्ञान एवं हाई टक्नोलोजी की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसी दशा में रेडियो के माध्यम से समय समय पर यात्री टिकटों के ओ० के० के संबंध में समाचार प्रसारित किये जायें ताकि एरोड्रोम तक जाने में व्यर्थ धन एवं समय बर्बाद नही करना पड़े ।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें विज्ञान एवं हाई टेक्नोलोजी की सुविधा उपलब्ध हैं । ऐसी दशा में रेडियो के माध्यम से यात्री टिकटों के ओ० के० के संबंध में समाचार प्रसारित किये जायें । ऐसी व्यवस्था करने से यात्रियों को काफी सुविधा मिल सकती है।

महोदया, इसके अलावा धारा 37 और 38 के अंतर्गत रुल्स एंड रेगुलेशंस बनाते समय उसमें इस बात का प्रावधान किया जाये कि टिकट की जो खिडकी है वह एरोड्रम के हाल के अन्दर खुली हुई है । यात्री लोग तो अंदर जाते हैं लेकिन जो उनसे मिलने वाले लोग टिकटों के संबंध में जानकारी करने जाते है उनको अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिये ऐसी खिड़कियां एरोड्रम के हाल के बाहर खुलती हुई होनी चाहिएं । टूरिस्ट स्पाट्स एवं धार्मिक स्थलों तक जाने के लिये कन्सेशनल टिकटों का प्रावधान किया जाये । यदि ऐसा किया जायेगा तो इससे यात्रियों की संख्या भी बढेगी और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी । महोदया, इसके अलावा टिकटों के संबंध में जो दुविधा है, इसके लिये ट्रैवलिंग एजेंटों पर प्रतिबन्ध लगाकर नेशनल एयर पोर्ट अथारिटी के द्वारा ही टिकटों की बिक्री का प्रावधान किया जाये ताकि यात्रियों को अधिक आर्थिक भार न सहना पड़े ।

इसके अलावा यात्रियों को बीच के स्टेशनों पर एरोड्रम के परिसर से बाहर जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए ताकि यात्री, जो हाल्ट का टाइम होता है, उसमें अपने लोगों से संपर्क स्थापित कर सकें । अगर वह परिसर के बाहर किसी कार्य के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहते है तो उनको बाहर जाने की सुविधा होनी चाहिए ।

इसके अलावा माननीय, शायद मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस मद पर 311.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि जब इस धनराशि का प्रावधान किया गया था उस वक्त यह बिल ड्राफ्ट हो चुका था या नही ? यदि बाद में ड्राफ्ट हुआ है तो ऐसी हालत में इसके लिये अलग राशि की व्यवस्था की आवश्यकता होगी और इसके लिये बजट में और प्रावधान करना होगा । यदि आपको इस काम को सुचारू रूप से चलाना है तो इसके लिये लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की जरूरत होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam Deputy Chairman, first of all I would like to thank all the Members who spoke on this Bill and supported the Bill. The very fact that not a single Member objected to the Bill means that the Bill was good and will serve the purpose for which it was created. Many Members spoke of the difficulties they had experienced regarding security, problems in getting tickets, reservation, failure of machines computer giving wrong information or computer not working resulting in people not getting tickets in time, in-flight service not being good complaints about food, canteen facilities not being there, more aerobridges at some of the airports, etc. I have already noted down these and I am sure that we will look into these and not look into these but I can assure you that no effort will be left to see that these things are put right. As a security aspect one Member suggested that a separate boarding pass should be made for MLAs and MPs. I don't think I would agree to this at all. Security is one thing and nothing is

[Shri Jagdish Tytler]

written on the face. I am not causing any aspersion on any MP or MLA. If the general public has to go through the proper security checks, the same thing should be there for an MP or an MLA. I have also said this that in respect of security, where the Ministers are concerned, they also will have to go through the proper procedure. Only if somebody is not well, I have already made arrangements with the Airports Authority to arrange for the ambulance or for a chair or even for a car to be allowed. There are only three or four exceptions, that is, the President, the Vice-President, the Prime Minister and the Chief Justice of India. Everybody else will have to go through all the procedures. With all these complaints coming in, I have already taken a decision yesterday that region-wise four Advisory Committees, consisting of the people who are using the airlines, will be set up and due consideration will be given to their suggestions and any complaints that they may bring forward and we will make sure that these will be put right.

Madam, I cannot give a guarantee for the planes running in time because many things are there which are not told to the public because of today's situation and from the security point of view we have to go through many processes which, I think, it is not wise for me to speak about here. That is a security matter which we are doing. But where a lapse occurs for security reasons, we are responsible and we have to come back to this House and answer it and we are answerable to the public.

Initially, Madam, when the debate was opened, a general impression prevailed that probably we are not happy with the CPWD or the UPSC and that is why we are trying to do this. No. The CPWD and the UPSC are too much burdened with so many works. But the airport or aviation work is such that we have to finish in time and this work has to be finished quickly. So, we are trying to lessen the burden of the CPWD and the UPSC and the other agencies and this is one of the reasons why we created this.

Madam, two or three honourable Members said some thing about clause 11. They said that the whole aim is to see that it is business-oriented. Now, I would like to say that the approach is business-oriented. We are a commercial organisation. But I can assure you that it will be service-oriented also.

Then, Madam, one of the Members mentioned about the Rajiv Committee Report and said that the Report has not been placed before Parliament. I think if the honourable Member goes to the Library, he will find that the Report is placed there in the Library.

With regard to the Vayudoot services linking the backward areas and the rural areas, this is one of the reasons why this service was created in the North-Eastern region, in the backward regions and the rural regions. That was why this was created and we are expanding in a very big way. I can assure the Members that as soon as the Dornier aircraft is manufactured in the country, we would be touching quite a number of places which are not touched today.

Madam, an honourable Member asked for an international service to Bhubaneswar. I would like to tell the honourable Members one thing: First of all, let them know that we have four international airports in the country and we do not have to go through any special process to declare or upgrade any airport in the country. Wherever there is a need, wherever there is traffic, we can declare that airport as an international airport or upgrade it for international service. As soon as we get proper traffic and enough number of aircraft, we will surely like to think about Bhubaneswar as one of the international airports.

AN HON. MEMBER: About Ahmedabad?

SHRI JAGDISH TYTLER: I have already mentioned about this. I have said that there are four international airports and with regard to Ahmedabad a study is being conducted and if it fulfils all the conditions, we would be very happy to have this thing also. Shri Jaswant Singhji had mentioned two very important things. About the security measure I have already answered. But he was feeling very uneasy that bodily search is done. I do not know which is the other way by which we can find out a person who is carrying anything. But a very good suggestion he has given. At international airports, when our people, Indians holding passports, etc., when they come they also stand in long lines. A separate line for immigrants could be had. I will see that this is done, because this is a good suggestion. We would like to see that this problem also is solved.

1 P.M.

Many Members spoke, and rightly so, that when they reach the airport in the morning and they have to catch a flight, they cannot get in because they do not have the ticket. I have already instructed the Department concerned to see that as soon as possible they should try to have the windows outside so that for the public entering the security zone these windows should be there to see if the tickets are available or not.

Mr. Bansal mentioned about Chandigarh not having any facilities for one-star or two-star hotel. One of the classes is in the Bill, so that when a situation does arise of this kind we will have the authority to build 5-6 rooms or 10-15 rooms or a small hotel where the people can stay in the night.

There was a little doubt on clauses 19 and 20. Clause 19 lays down that the funds will be kept in scheduled banks. Clause 20 provides that the profits after deducting the reserve fund and the general reserve will be paid to the Government. Since the Authority will be funded by the Government, I do not think there is anything in the Bill.

There have been many complaints about computer booking. While the computer was new in our country, the kinds of complaints received initially when the computer was installed and what they are now have been reduced by 90 per cent. We have 10 per cent problem. (*Interruption*). We would like to assure the Members that we would like to get rid of this kind off delay also and see that the computer works as it should be working.

Mr. Thangabalu spoke about the facilities at Salem Tuticorin, Tiruchy and Coimbatore. Now, I had myself visited Salem recently, and I had asked the Chief Minister and also the Minister of the Tamil Nadu Government to please give us the land so that we can start this work. As soon as the Government identifies the land, we would like to start thinking at least whether we can give an airport there or not.

Shri Shah also complained about the instrument landing and the radar system not working at the airport. I am sure he should have known that such a big cyclone we had in Madras that the whole city was under water. Even the Chief Minister had to go on a boat to another place. So, no doubt the instruments were not working. But the instrument landing system and also radar we have already put right, and we have also taken care to see if these could be put on a higher level so that in future— not that we wish it—if ever we have a situation like this, at least the system on the ground for the aircraft should be working.

Shri Radhakrishnanji mentioned that bridges — tubes, as he mentioned — should be there so that he can reach from the aeroplane to the airport; he does not like to go by buses. At Delhi and Bombay international airports, we are doing it. I do not think it would be possible in the local airports until it may be 20-30 years.

[Shri Jagdish Tytler]

I had already mentioned about X-Ray machines. Our plan is to instal X-Ray machines in all the airports. We also had complaints from many places that the X-Ray machines are not working in many places. I think instructions have already gone to see that this kind of thing should not be there because it is a very important part of our security.

Most of the other problems which the hon. Members have mentioned are of a general nature about which I had spoken initially. As far as the Shimla Ajrport is concerned, the work is going on. We hope that by next summer or may be end of summer we will have the Shimla Airport working. We hope so. The work is going on at great speed.

About the concession, we do give concessions. I have announced yesterday that our Prime Minister was very keen that sports people who take part in sports in Delhi or in any other part of the country and who are connected with Olympics or the Asiad or who take part in any other internationally recognised sports will be given the concession to travel free to the venue of the sports. Such concessions are being given. I would like to qualify this by saying that the sportsmen who have won gold medal or silver medal or bronze medal will be given this facility.

We are looking into the catering part of it. Many people have complained about it. This is one of our first priority. Catering, courteous service and security are our priorities. We are giving our utmost attention to this thing. I am sure that we will improve on these things. (*Interruptions*).

Clause 7 is about reappointment will depend on the ability of the Members. It will depend on how he has worked during his tenure. There is no clause saying that he may be given reappointment only for 3 months. If the Member is good and useful to the Authority, we do not mind extending his term as long as we feel that he is useful. I have answered most of the questions.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Recently the Vayudoot service was withdrawn from Surat. I would like to know whether the hon. Minister will put Surat on the air map of India.

SHRI JAGDISH TYTLER: I have mentioned earlier that we are prepared for everything. But we must have the traffic.

SHRI RAOOF VALIULLAH: Have you conduited a survey of the air traffic in Surat?

SHRI THANGABAALU (Tamil Nadu): The Members of Parliament from Tamil Nadu have requested for a direct flight beween Madras and Delhi. It was already there, but it was discontinued. Please consider that immediately. Madras is a very important city in the South and many people are suffering. They have to go *via* Hyderabad in the mornings and evenings. You must see that there is a direct flight between Madras and Delhi.

SHRI JAGDISH TYTLER: Many hon. Members from Tamil Nadu in both the Houses have asked for it. When it was mentioned in the Lok Sabha, I contacted our M.D. and asked him to see at the earliest, as soon as the first aircraft is available, that this service is provided. We would like that a direct Airbus should be there.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): While

replying to the debate, the hon. Minister said that there are only four international airports in the country and there is no proposal to make any other airport as international airport. But he has already committed that Hyderabad will be considered for that and the flights will start from 19th December.

SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to clear again. I said and I repeat that there are only four international airports in our country. But there is no reason that wherever there is a need we cannot extend the international flights and use that airport, particularly any airport upgraded to that level, and use that. We do not have to declare an airport as an international airport. And I would like to tell you that on the 19th, yes, we are starting in Hyderabad the first flight. And I would like to invite you on the 19th flight from Bombay to Hyderabad, and you will know.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of an Authority for the management of aerodromes and civil enclaves whereat domestic air transport services are operated or are intended to be operated and of all communication stations and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill. There is one amendment by Shri Gopalsamy to Clause 2. He is not here.

The question is:

That clauses 2 to 42 stand part of the ill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 42 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नार्थ-इस्टर्न रीजन, पिछड़े इलाके के बारे में काफी चिंतित हैं । यह सही बात है और चिंतित होना भी चाहिए । लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसी हमारी माननीय सदस्या मनोरमा जी ने चर्चा भी की है, पटना के बारे में कि वह कैपिटल है, उसके एअरपोर्ट को हम देखेंगे तो लगेगा कि जैसे सब-जिला या टाऊन का एअरपोर्ट है, वहां कोई सुविधा नहीं है । दुर्भाग्यवश वहां से हमारे ए०पी० शर्मा जी मंत्री रहे, भागवत झा आजाद जी मंत्री रहे, लेकिन चाहे रेल की बात हो या हवाई जहाज की बात हो कुछ नहीं हुआ । इसी सिलसिले में उपसभापति महोदया, मैं कहूंगा कि सारे बिहार में इंडियन एअर-लाइन्स दो ही जगह टच करता है, रांची और पटना, जहां साढ़े सात करोड़ की आबादी है और हमको आप कहते हैं कि पिछड़ा , अरे, पिछड़ा तो आपने जानबूझकर हमें बनाया हुआ है । आप कहते हैं कि कोई एअर-ट्रेफिक नहीं है । आप जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो एअर-ट्रेफिक कहां से पैदा होगा । जब आप लाइन बिछाएंगे, तब लोग जाएंगे न ? इसलिए मैं कहूंगा कि उत्तरी बिहार ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदया, एक मिनिट, आप जानती है कि उत्तरी बिहार सबसे पापुलेटिड एरिया हैं और वहां सतरह जिला में कहीं भी एअर-पोर्ट नहीं है, कहीं भी जहाज नहीं उतरता है । पहले ए-फोर-जीडी-वनवन/फोर जी०डी०-वन टू जाती थी मुज्जफरपुर होकर...(**व्यवधान**)...

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे जाना है, कृपया...

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र आपने आथराइज करके जाना है, तो जाइए...

उपसभापति इनका जहाज छूट जायेगा...

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : छूट जाएगा तो क्या ! हम लोग हमेशा के लिये छूट जाते हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था करें कि यह ए-फार-वन जो डरो-वन जो मुज्जफरपुर जाया करती थी.....

उपसभापति : आप चिट्ठी लिखकर भेज दीजिए, मंत्री जी वह जरुर करेंगे।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : ठीक हैं तो उसके लिये उत्तरी बिहार के लिये कुछ निश्चित रूप से कृपया करें।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (West Bengal): Madam.... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can write a letter to the Minister.

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 2ND DECEMBER, 1985

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Kesri.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Busines in the House during the week commencing 2nd December, 1985, will consist of:

1. Consideration and passing of the Citizens (Amendment) Bill, 1985, as passed by Lok Sabha.

2. Discussion on the 23rd, 24th, 25th, 26th and 27th Reports of the Commissioner for Schedule Castes and Schedule Tribes and the 1st, 2nd, 3rd and 4th Reports of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3. Consideration and passing of the following Bills as passed by Lok Sabha:—

(a) The Inland Waterways Authority of India Bill, 1985

(b) The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Bill, 1985.

(c) The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Bill 1985.

4. Consideration and return of the Appropriation Bill relating to the Supplementary Demands for Grants (General) for 1985-86.

5. Consideration and passing of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 1985, as passed by Lok Sabha.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam, today we are having a very serious situation in Sri Lanka. A large number of Tamils are being killed. I want to suggest that we should have a discussion on this very serious situation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The international situation is going to be discussed in the House. At that time we can discuss this matter also.

SHRI SITARAM KESRI: We are going to discuss the International Situation on the 10th of December.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 P.M.